रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33001/98

REGISTERED NO. D. L.—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण भाग में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 1999/पौष 12, 1920
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 1999/PAUSA 12, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1998

स्टाम्प

का०आ० 1.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को मात्र चार लाख सैंतीस हजार दो सौ बीस रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त निगम द्वारा दिनांक 15-5-98, 16-5-98 25-5-98 तथा 12-6-98 को आवंटित किए गए आठ करोड़ चौहत्तर लाख तैंतालीस हजार नौ सौ अड़सालीस रुपये के समग्र मूल्य की विशिष्ट संख्या वाले 2085 से 2090 तक क्रमशः आई. एफ. सी. आई. प्रमाण-पत्रों के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के रूप में जमा प्रमाणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 41/98-स्टाम्प फा. सं. 15/23/98-वि. क.]

अपर्णा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 11th December, 1998

STAMPS

S.O. 1.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Industrial Finance Corporation of India Limited, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees four lakh thirty seven thousand two hundred twenty only chargeable on account of the stamp duty on Certificates of Deposits in the nature of promissory notes described as

do so. It is not the case of the workman that the Presenting Officer or the foreman under whom he works did not inform him the date. Infact there is no cogent evidence for coming to the conclusion that he was not aware of the hearing date.

9. The inquiry officer had given his report which is at Exhibit-15/12 on 7-12-89. It relate to the chargesheet dtd. 4th July, 1989 for an offence committed on 29th March '89. The workman accepts that he received the report. He had not taken any steps after receiving the report. If really the inquiry would have been conducted in his absence naturally immediately thereafter he would have approached the management contending that he was not informed in respect of the inquiry. As he had not done so I am not inclined to accept that the inqury was conducted behind his back.

10. Exhibit-15/6 is a statement of the worker by which he accepts that he was found in possession of the brown sugar and the smoking material as alleged in the Panchanama. He did not depose that the material mentioned there in was not found in his possession. From the testimony of the workman I do not find that the inquiry officer conducted the inquiry against the Principles of Natural Justice.

11. Looking to the inquiry report (Ex-15/2) it is very clear that the inquiry officer relied upon the Chief Security Officers report dtd. 31-3-89 the confessional statement of the delinquent and the panchanama dtd. 29-3-89. He has also relied upon the oral testimony of Surendra Kumar. He in categorical term has stated that the workman was found in possession of the articles stated in the Panchanama viz. brown sugar and the smoking articles. The Inquiry Officers report is well reasoned and findings are based on the evidence before him. I do not find any perversity for the same. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The domestic inquiry which was held against the workman was as per the Principles of Natural Justice.

The findings of the inquiry officer are not perverse.

S.B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1998

का.आ. 51.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जनवरी, 1999 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम, के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"कोयम्बतूर जिला के अविनाशी तालुक में राजस्व ग्राम अविनाशी, पोलगौर, सेम्बियनल्लूर, तेक्कलूर, पुदुप्पालयम, वेलायुतम पालयम, नम्बियमपालयम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[सं. : एस-38013/27/98-एस.एस.-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 1998

S.O. 51.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st January, 1999 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :

"Areas comprising the Revenue Villages of Avinashi, Palangarai, Sembianallur, Thekkalur, Pudupalayam, Velayuthampalayam and Nembiampalayam in Avinahi Taluk of Coimbatore."

[No. S-38013/27/98-SS-I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1998

का.आ. 52 :—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1657 तारीख 28 मई, 1992) (जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में 20 जून, 1992) को प्रकाशित हुई थी को अधिक्रांत करते हुए, एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

सलाहकार समिति

1.	संघ का श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, श्रम मंत्रालय	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय (बाल और महिला श्रम का प्रभारी).	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास विभाग	पदेन सदस्य
5.	सलाहकार, श्रम और नियोजन विभाग, योजना आयोग	पदेन सदस्य
6.	सचिव, श्रम विभाग आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	पदेन सदस्य
7.	सचिव, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकर, लखनऊ	पदेन सदस्य
8.	सचिव, श्रम विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली	पदेन सदस्य
9.	सदस्य सचिव, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10.	श्री विधवा मिश्र बहल अखिल भारतीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, 70 शिवाजी मार्ग, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली ।	अशासकीय सदस्य

11. डा. (सुश्री) एन हंसा, अपर सचिव,
फेडरेशन आफ इंडियन चम्बर्स आफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली। अशासकीय सदस्य

12. श्रीमती रेणुका देवी बरकातकी, अध्यक्ष, आई. एन.
टी. यू. सी. असम शाखा, के. सी. सेन, मार्ग,
पल्टन बाजार, गुवाहटी, असम। अशासकीय सदस्य

13. कु. मंगलाम्बा राव, राष्ट्रीय कार्यपालक सदस्य
भारतीय मजदूर संघ, केयर आफ बी.एम. एस.
कार्यालय, सूबदार छातारम मार्ग, बंगलौर अशासकीय सदस्य

14. कुमारी सुचित्रा महापात्र, महा सचिव,
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ,
एन. ए. सी. कालोनी, मालाशहली ईकाई 3,
भुवनेश्वर। अशासकीय सदस्य

15. श्रीमती गीता जयंत गोखले, 181ए, राम निवास,
जे. बी. इन्दुलकर मार्ग, विले पार्ले (यू.) मुम्बई अशासकीय सदस्य

16. सुश्री जया अरुणाचलम, अध्यक्ष, वर्किंग वूमेनफोरम
(भारत), 55, भीमसेन गार्डन मार्ग, मायलापुर,
चेन्नई। अशासकीय सदस्य

17. सुश्री मनाली शाह, सेल्फ एम्पलायड वुमेनस
एसोसिएशन (एस.ई. डब्ल्यू. ए.), सेवा रिसपशन
सेंटर विक्टोरिया गार्डन के सामने भद्रा, अहमदाबाद अशासकीय सदस्य

18. सुश्री मंजू श्री मिश्रा, इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट
इंडिया हैबिटेट सेंटर, ईस्ट कोर्ट अप्पर ग्राऊंड फलोर,
जोन 6, लोधी रोड, नई दिल्ली। अशासकीय सदस्य

19. श्री सुवर्शन सरीन, अध्यक्ष, दिल्ली राज्य औद्यो-
गिक विकास निगम, लि., एन .ब्लाक, बांम्बे लाईफ
बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली। अशासकीय सदस्य

20. श्रीमती सुकवा मिश्रा
संसद सदस्य (लोक सभा) अशासकीय सदस्य

21. कुमारी फरीदा टोपनों, संसद सदस्य (राज्य सभा) अशासकीय सदस्य

22. समिति के अशासकीय सदस्य (यों) का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

[सं. ए-42011/25/97-सी. एंड डब्ल्यू एल-II अनुभाग]
प्रीत वर्मा, निदेशक

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd December, 1988

S.O. 52.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1657 dated 28th May, 1992 (published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on the 20th June, 1992), the Central Government hereby constitutes the Central Advisory Committee, consisting of the following members, namely :

Advisory Committee

1. Union Minister for Labour. — Chairperson
2. Secretary, Ministry of Labour. — Ex-Officio Member
3. Joint Secretary, Ministry of Labour (incharge of child and women labour). — Ex-Officio Member
4. Joint Secretary, Department of Women and Child Development. — ,,
5. Adviser, Labour & Employment Division, Planning Commission. — ,,
6. Secretary, Labour Department Government of Andhra Pradesh. Hyderabad. — ,,
7. Secretary, Labour Department Government of Uttar Pradesh, Lucknow. — ,,
8. Secretary, Labour Department, National Capital Territory of Delhi, Delhi — ,,
9. Member Secretary, National Commission for Women, 4, Deen Dayal Upadhaya Marg, New Delhi. — ,,
10. Shri Vishwa Mittra Bahl, All India President, Laghu Udyog Bharti, 70, Shivaji Marg, Industrial Area, New Delhi. — Non-Official Member
11. Dr. (Ms.) N. Hamsa, Additional Secretary, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi. — ,,
12. Mrs. Renukadevi Barkataki, President INTUC Assam Branch, K. C. Sen Road, Paltan Bazar, Guwahati (Assam). — ,,
13. Km. Mangalamba Rao, National Executive Member. Bhartiya Mazdoor Sangh, C|O BMS Office, Subedar Chhataram Road, Bangalore. — ,,
14. Kumari Suchitra Mahapatra, General Secretary, Akhil Bharatiya Anganwadi Karmachari Mahasangh, NAC Colony, Malishali-2, Unit-3, Bhubaneshwar. — ,,
15. Smt. Geeta Javant Gokhale, 101-A, Ram Nivas, J. B. Indulkar Marg, Ville Parle (E), Mumbai. — ,,
16. Ms. Jaya Arunachalam, President, Working Women's Forum (India), 55, Bhimasena Garden Road, Mylapore, Chennai. — ,,
17. Ms Manali Shah Self Employed Women's Association (SEWA) Sewa Reception Centre, Opp Victoria Garden, Bhadra, Ahmedabad. — ,,
18. Ms Manjushree Mishra, Institute of Social Studies Trust, — ,,

India Habitat Centre East Court Upper Ground Floor, Zone 6, Lodhi Road, New Delhi.

19. Shri Sudarshan Saleen, Chairman, Delhi State Industrial Development Corporation Ltd., N-Block, Bombay Life Building, Connaught Circus, New Delhi. — Non-Official Member

20. Smt. Sukhda Misra, Member of Parliament) (Lok Sabha). — "

21. Miss Farida Topno, Member of Parliament, (Rajya Sabha).

2. The terms of office of non-official Member(s) of the Committee shall be two years.

[No. A-42011/25/97-C&WL-II Section]
PREET VERMA, Director

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1998

का.आ. 53.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (VI) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1387 दिनांक 1 जुलाई, 1998 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 1998 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (VI) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 1999 से छह मास की और कालावधि लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/13/97-आई.आर. (पी. एल.)]
एच. सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1998

S.O. 53.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1387 dated 1st July, 1998 the Iron Ore Mining Industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 1st July, 1998;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 1st January, 1999.

[No. S-11017/13/97-IR(PL)]
H. C. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999